OFFICE OF THE APPELLATE AUTHORITY, under RTI Act, HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, BENCH AT INDORE

RTI Appeal No. 05/2025

Vs

Order (Delivered on 16th June 2025)

This appeal has been preferred u/s. 19 (1) of the RTI Act., 2005 by the appellant Mr. Krishnalal Nathulal Bhawsar being aggrieved by the order passed by the State Public Information Officer, High Court of M.P., Bench at Indore dated 26/05/2025 by which application of applicant was decided with direction that he had not filed prescribed form- 'A' and failed to affix/attested his photograph and Indian Non-Judicial Stamp of Rs. 50/-.

The brief facts of application is, under RTI act, for seeking information as mentioned in his applications Para No. (1) to (6).

"1. सीनियर सिटीजन के प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई के संबंध में जारी दिशा—निर्देशी के संबंध में कानून प्रक्रिया को दर्शाने वाले पत्री, परिपत्रओं या आदेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि संबंधित वकील— बगैर अपने क्लाइंट के संज्ञान में लाये और गैर उसकी सहमति के कोर्ट में केस के संबंधित कोई कथन नहीं कर सकते। इस व्यवस्था को हाइकोर्ट में एक्जीक्यूट करने के लिए जारी दिशा—निर्देशों एवं आदेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। यदि वकील उक व्यवस्था को वायलेट करते हैं ती कार्रवाई की रूप रेखा से संबंधित जानकारी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

- 3. माननीय हाईकोर्ट में सीनियर सिटीजन के प्रकरणी में शासकीय अधिवक्ता अधिकतम कितनी बार तक 'एडजस्टमेट' करा सकते हैं? और बैंच में लगने के बाद, प्रकरण कितने मिहनों तक 'नाट रीच्ड' के माध्यम से लंबित रखा जा सकता है? सुलम संदर्भ हेतु wp—20065/2017 के स्क्रीन शाट्स सलग्न हैं इस wp से wp- 11552/2019 क्लिब्ड है। प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। इस प्रक्रिया को अजाम देने वाले कर्मचारी या अधिकारी महोदय का नाम एवं पद की जानकारी देने की कृपा करें।
- 4. माननीय बैच में प्रकरण लगने के बाद सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन के प्रकरणों में 'नाट रीच्ड' की अविध में अंतर की कोई निर्धारित व्यवस्था है? तत्संबिधत जानकारी प्रमाणित रूप में उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 5. क्या ऐसा नियम कानून है कि बगैर कारण के सीनियर सिटीजन के प्रकरणों की निर्धारित अविध से अधिक लिबत नहीं रखा जा सकता है, निर्धारित अविध और अधिकतम अविध की प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन का जीवन अत्यिधक अनिश्चित माना जाता है।
- 6. उक्त जानकारियों में ऐसी कोई जानकारी, जिससे माननीय हाईकोर्ट की अवमानना का प्रश्न जुड़ता है तो कृपया वह जानकारी उपलब्ध न करायें। मेरे लिए माननीय हाईकोर्ट का सम्मान मागी गई जानकारी से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।"

After receiving of application, SPIO has rejected the application mainly on the ground of insufficient fee and inappropriate format.

Applicant filed this appeal and urged for information above.

Heard both the parties.

Perused the order of SPIO which reveals that application of applicant is rejected only on technical ground. There is no decision on merit of the application.

It is true that as per High Court of M.P. Rules, 2008, authority shall charge fee Rs. 50/- and application should be in appropriate form but it is a procedure. If any deficiency is there, the authority could sought the applicant to cure the defects.

Authority could direct the applicant to pay the deficient amount and file proper format.

So, in this matter in my view, it is incumbent on authority that applicant should be given a chance for rectifying deficiency and if he failed, authority can reject the application, but in this matter there is no evidence for giving the chance to the applicant.

So, on the above discussion, I found that applicant should be given one chance. Thus appeal is allowed and authority is directed to give a chance to applicant to rectifying the defects and if applicant rectifying that defects that is proper format of application and proper fee, then his application be decided on merit within stimulated time given by Act.

Copy of this order be sent to Joint Registrar (M), High Court of M.P., Bench at Indore for necessary action and information. A copy of this order be also provided free of cost to the appellant/applicant and also to the SPIO for information and necessary action.

As per Section 19(3) of the RTI Act, 2005, appellant/applicant may file an appeal to the Hon'ble Appellate Authority (State Information Commission, Bhopal) within 90 days of the issuance of this order.

(ANOOP KUMAR TRIPATHI)
APPELLATE AUTHORITY